बाह्य सहायता से प्रस्तावित परियोजनाएँ:–

(1) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित **उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना** की लागत रू0 3500.00 करोड़ आंकलित की गयी है, जिसमें 30 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना 5–5 वर्षों के तीन चरणों में प्रस्तावित है। परियोजना की कुल अवधि 10 वर्ष होगी। परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में दो वर्षों का एवं द्वितीय तथा तृतीय चरण में तीन वर्षों का ओवरलैप होगा। इस परियोजना में कुल मिलाकर मार्गों का उच्चीकरण 2388 किमी0 में तथा सतह सुधार 1261 किमी0 में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट सचिव, मार्ग परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को लो0नि0वि0 द्वारा 11 जून, 2013 में प्रेषित की गई, जिसे 08.08.2013 में परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। विश्व बैंक का पत्र सरकार को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट को विश्व बैंक को संस्तुति सहित अग्रसारित कर दिया गया है तथा एक सप्ताह के प्राप्त होते ही 03 माह के अन्दर कन्सल्टेन्ट का चयन कर डी0पी0आर0 बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। 15 से 18 माह के अन्दर परियोजना का प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना बताई गई। विश्व बैंक दल की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के साथ बैठक करने के साथ ही लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग तथा गृह/पुलिस विभाग के साथ भी बैठकें की गईं तथा प्रत्येक विभाग के कार्यों हेतु एक समयावधि निर्धारित की गई है। परियोजना के अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु 04 कन्सल्टेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जा चुका है।

(2) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित होने वाली **उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना** को एशियाई विकास बैंक से वित्त–पोषित कराये जाने हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 1138 किलोमीटर लम्बाई के 27 प्रमुख जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु रू0 2670.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परियोजना दो चरणों में प्रभावी होगी तथा प्रत्येक चरण की अवधि 04 वर्ष होगी। प्रदेश के कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित कुल 3279.00 किमी सड़क में से 1138.50 किमी0 सड़कों का विकास प्रस्तुत परियोजना के तहत किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का प्रस्ताव सक्षम स्तरों से अनुमोदित कराकर सड़क परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 29.08.2013 को प्रेषित किया जा

चुका है। परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित सिविल कार्यों की लागत के 50 प्रतिशत कार्यों हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति ने दिनांक 02.07.2014 को हुई बैठक में न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव देने वाले कन्सल्टेन्ट फीडबैंक इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, गुरगॉव को उक्त कन्सल्टेन्सी कार्य आवंटित कर दिया है।

(3) विश्व बैंक से वित्त–पोषण हेतु प्रस्तावित **प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट** के माध्यम से घरेलू पर्यटन स्थलों का विकास, स्थानीय जनता के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना तथा ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र बौद्ध सर्किट तथा ब्रज आगरा कॉरीडोर हैं। इस योजना की लागत रू0 1800 करोड़ है, जिसमें से 30 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस परियोजना से संबंधित प्रारम्भिक अध्ययनों के लिये वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 125.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। परियोजना हेतु प्रारम्भिक अध्ययन कराने तथा संगठनात्मक–ढ़ाचे (एस0पी0सी0यू0) के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य–क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रमुख पहुॅच मार्गो/सड़क मार्गो के सुधार का कार्य लोक निर्माण विभाग की विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना है।

(4) नगर विकास विभाग द्वारा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत **सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना** प्रस्ताव तैयार किया गया है। परियोजना की अवधि 05 वर्ष एवं कुल लागत रू0 2410.00 करोड़ है। परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के 65 जिलों के 177 शहरों/नगरों में ठोस अपशिष्टों के प्रबन्ध में सुधार लाये जाने हेतु तैयार की गयी है। परियोजना की कुल लागत का 70 प्रतिशत अंश विश्व बैंक बाह्य सहायता के रूप में तथा शेष 30 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नोडल कमेटी की बैठक दिनांक 20.05.2013 को प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जा चुकी है। प्रस्ताव मा0 मंत्रि–परिषद के अनुमोदनोपरान्त विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त किए जाने हेतु नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जा चुका है।

(5) ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत **उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र क्षमतावर्द्धन परियोजना** विश्व बैंक से बाह्य सहायता प्राप्त किये जाने हेतु तैयार की गयी है। परियोजना प्रस्ताव की कुल लागत 3000.00 करोड़ है। यह धनराशि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपनी अंशपूंजी से वहन की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में विद्युत नेटवर्क के सुधार, तकनीकी एवं वाणिज्यिक सुधार तथा नेटवर्क सुदृढ़ीकरण हेतु तथा पारेषण क्षेत्र में नयी लाइनों एवं उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये तथा लोड फ्लो स्टडीज़ के लिये ऋण

उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना की अवधि 05 वर्ष प्रस्तावित है। प्रारम्भ में नोयडा एवं मथुरा के लिए एक तकनीकी अध्ययन विश्व बैंक अपने खर्चे से करायेंगे। इन शहरों में आवश्यक सुधार हेतु निवेश वितरण कम्पनियों द्वारा किया जाएगा। पारेषण क्षेत्र में भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा तकनीकी परामर्श के लिए धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किए जाने की प्रक्रिया में है।